



स्मार्ट ग्राम पंचायत

प्रलिस के लयि:

[PM-वाणी](#), [राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभयान](#), [पंचायती राज संस्थान \(PRI\)](#), [सतत विकास लक्ष्य](#), [भारतनेट](#)

मेन्स के लयि:

भारत के डजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) में PM-WANI की भूमिका, डजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI), ग्रामीण डजिटल साक्षरता में सुधार, सरकारी नीतयों और हस्तक्षेप

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने बहिर के बेगुसराय ज़िले के पपरौर ग्राम पंचायत में **स्मार्ट ग्राम पंचायत**: ग्राम पंचायत के डजिटलीकरण की दशा में क्रांती परयोजना का उद्घाटन कया। यह पहल **ग्रामीण भारत में डजिटल सशक्तीकरण** की दशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रगती है।

स्मार्ट ग्राम पंचायत परयोजना क्या है?

- इस परयोजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की कनेक्टविति में एक आदर्श परिवर्तन के साथ बेगुसराय की सभी ग्राम पंचायतों तक **PM-वाणी (प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस)** सेवा पहुंचाना है।
 - बेगुसराय अब **PM-वाणी योजना** के तहत सभी ग्राम पंचायतों को वाई-फाई सेवाओं से लैस करने वाला बहिर का पहला ज़िला बन गया है।
- इसे संशोधित **राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभयान (RGSA)** के तहत वतित पोषित कया गया है। इस परयोजना का लक्ष्य बहिर में बेगुसराय और रोहतास ज़िलों की 37 ब्लॉकों में 455 ग्राम पंचायतों को वाई-फाई सेवा पहुंचाना है। इसका कार्यान्वयन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कया गया।
- स्वास्थ्य, शक्ति और कौशल जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लयि प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया गया है।
 - छात्र, किसान, कारीगर और **महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG)** को इस पहल से लाभ प्राप्त होगा।
- समय के साथ परयोजना के प्रभाव को बनाए रखने के उद्देश्य के साथ संचालन और रखरखाव (O&M) के लयि सुदृढ़ तंत्र स्थापित कया जाएगा।
- परयोजना का उद्देश्य **ग्रामीण-शहरी वभिजन को पाटना**, **स्थानीय स्वशासन** में उत्तरदायित्व और दक्षता को बढ़ावा देना तथा डजिटल फुटप्रिंट के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाना है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभयान (RGSA):

- RGSA पंचायती राज मंत्रालय की एक योजना है, जसे वर्ष 2018 में लॉन्च कया गया था। इसे बेहतर बनाते हुए RGSA की **केंद्र परायोजति योजना** को **पंचायती राज संस्थाओं (PRI)** के **नरिवाचति प्रतनिधियों (ER)** की क्षमता नरिमाण के लयि वर्ष **2022-23 से वर्ष 2025-26** की अवधि के साथ कार्यान्वयन के लयि मंजूरी दी गई।
- संशोधित RGSA का प्राथमिक उद्देश्य **सतत विकास लक्ष्यों (SDG)** को पूरा करने के लयि पंचायतों की शासन क्षमताओं को वकिसति करना है। योजना के तहत पंचायतों के नरिवाचति प्रतनिधियों को चुनाव के बाद छह महीने के भीतर बुनयिदी अभविन्यास प्रशक्ति तथा दो वर्ष के भीतर पुनश्चर्या प्रशक्ति सुनश्चित कया गया है। राज्य घटकों के लयि **केंद्र और राज्यों की हसिसेदारी क्रमशः 60:40** के अनुपात में होगी, पूर्वोत्तर तथा पहाड़ी राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर के अतरिकित जहाँ केंद्र एवं राज्य का अनुपात **90:10** होगा। **सभी केंद्रशासति प्रदेशों के लयि केंद्रीय हसिसा 100%** होगा।
- RGSA का मूल उद्देश्य:
 - ई-गवर्नेंस** और **SHG के स्थानीयकरण** पर वभिनिन स्तरों पर **पंचायत-SHG अभसिरण** तथा प्रशक्ति को सुदृढ़ करना।
 - इंटरैक्टिव क्षमता नरिमाण और मानकीकृत प्रशक्ति के लयि उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना। डजिटल साक्षरता और नेतृत्व

पीएम-वाणी क्या है?

परिचय:

- दिसंबर 2020 में [दूरसंचार विभाग \(Department of Telecom - DoT\)](#) द्वारा लॉन्च की गई पीएम-वाणी (PM-WANI), देश भर में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में एक मजबूत डिजिटल संचार अवसंरचना स्थापित करने के लिये सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट तक पहुँच में वृद्धि के उद्देश्य से शुरू की गई एक प्रमुख योजना है, जो कोई भी [इकाई राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 \(ational Digital Communications Policy - NDCP\)](#) के अनुरूप हॉटस्पॉट स्थापित कर सकती है ।

पीएम-वाणी (PM-WANI) इकोसिस्टम:

सार्वजनिक डेटा कार्यालय (PDO):

- PDO वह इकाई है जो वाई-फाई हॉटस्पॉट की स्थापना, रखरखाव और संचालन करती है तथा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं या इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से इंटरनेट बैंडविडिथ प्राप्त कर उपयोगकर्ताओं को **अंतिम-मील कनेक्टिविटी** (अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुँच) प्रदान करती है ।

पब्लिक डेटा ऑफिसर एग्रीगेटर (PDOA):

- PDOA वह इकाई है जो PDO को प्राधिकरण और लेखांकन जैसी **एग्रीगेशन सर्विसिज़** प्रदान करती है तथा उन्हें अंतिम उपयोगकर्ताओं को सेवाएँ प्रदान करने में सुविधा प्रदान करती है ।

एप प्रदाता (App Provider):

- यह वह इकाई है जो **उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करने और इंटरनेट सेवा तक पहुँच के लिये PM-WANI के अनुरूप वाई-फाई हॉटस्पॉट खोजने तथा प्रदर्शित करने हेतु एक एप्लीकेशन विकसित करती है** एवं संभावित उपयोगकर्ताओं को प्रामाणित भी करती है ।

केंद्रीय रजिस्ट्री:

- यह वह इकाई है जो एप प्रदाताओं, PDOA और PDO का वविरण रखती है । वर्तमान में इसका रखरखाव **सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (C-DoT)** द्वारा किया जाता है ।

PM-WANI के लाभ:

- PM-WANI ग्रामीण क्षेत्रों में **ब्रॉडबैंड उपलब्धता और सामर्थ्य को बढ़ावा** देगा, उद्यमशीलता तथा डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देगा । यह [भारतनेट परियोजना](#) का पूरक है ।
- यह **5G** जैसी मोबाइल प्रौद्योगिकियों की तुलना में इंटरनेट एक्सेस हेतु एक कफायती और सुविधाजनक विकल्प प्रदान कर सकता है, जिसके लिये उच्च नविश तथा सदस्यता लागत की आवश्यकता होती है । यह इंटरनेट बाज़ार में नवाचार और प्रतस्पर्द्धा को प्रोत्साहित कर सकता है ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा/से भारत सरकार के 'डिजिटल इंडिया' योजना का/के उद्देश्य है/हैं? (2018)

- भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन, जैसा कि चीन ने किया ।
- एक नीतगित ढाँचे की स्थापना जिससे बड़े आँकड़े एकत्रित करने वाली समुद्रपारीय बहु-राष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके कवि हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के अंदर अपने बड़े डेटा केंद्रों की स्थापना करें ।
- हमारे अनेक गाँवों को इंटरनेट से जोड़ना तथा हमारे बहुत से विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख पर्यटक केंद्रों में वाई-फाई की सुविधा प्रदान करना ।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- केवल 1 और 2
- केवल 3
- केवल 2 और 3
- 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

प्रश्न 2. पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? (2015)

1. विकास में जन-भागीदारी
2. राजनीतिक जवाबदेही
3. लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
4. वित्तीय संग्रहण (फाइनेंशियल मोबिलाइज़ेशन)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1, 2 और 3
- (b) केवल 2 और 4
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न. "चौथी औद्योगिक क्रांति (डिजिटल क्रांति) के प्रादुर्भाव ने ई-गवर्नेंस को सरकार का अवभाज्य अंग बनाने की पहल की है"। वविचन कीजिये। (2020)

प्रश्न. भारत में स्थानीय शासन के एक भाग के रूप में पंचायत प्रणाली के महत्त्व का आकलन कीजिये। विकास परियोजनाओं के वित्तीयन के लिये पंचायतें सरकारी अनुदानों के अलावा और कनि स्रोतों को खोज सकती हैं? (2018)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/smart-gram-panchayat>

